मेहनतकशों का पैग़ाम
मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

खट्टर दिखायें रोजगार सपना	3
कृष्णपाल का जुमला	4
जनसंपर्क मोदी	5
तृतीयलिंगी समाज	6
अरनब-रामदेव ठग जोड़ी	8

वर्ष 34 अंक -7 फ़रीदाबाद 30 दिसम्बर-5 जनवरी 2019 फोन - 9999595632 ₹ 2.50

सुप्रीम कोर्ट का अजब अरावली संरक्षण : कांत एन्कलेव को उजाड़ रही और पंचतारा होटल बनवा रही

फ़रीदाबाद (म.मो.) सितम्बर माह में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली बार्डर से सटे कांत एन्कलेव के उन बसे-बसाये घरों को तोड़ दिया जाये जो 1992 के बाद बने हैं। यह आदेश पर्यावरण एवं अरावली संरक्षण के नाम पर दिया गया है। विदित है कि यह पूर्णतया विकसित कॉलोनी है। यहां सड़क, सीवर, पानी व बिजली की पूरी व्यवस्था बरसों पहले कर दी गयी थी। भजनलाल व उनके बाद आई लगभग सभी सरकारों ने इस कॉलोनाइजर को भरपूर सहयोग देते हुए तमाम तरह के आवश्यक लाइसेंस तथा अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किये थे। वह बात अलग है कि इस सहयोग के बदले तमाम सरकारों ने पूरी कीमत वसूली थी।

उस दौर में हरियाणा सरकार से उठकर मामला जब न्यायपालिका के पास पहुंचा तो तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायधीश अहमदी ने भी अपनी कीमत वसूलकर कॉलोनाइजर को माकूल राहत प्रदान की थी। इसके लिये उसने अहमदी की बेटी को अपना वकील बना लिया था। वकील बेटी को हर माह नकद फीस मिलती थी जिसे वह कॉलोनाइजर को ही उस प्लॉट के बदले बतौर किश्त देकर रसीद प्राप्त कर लेती थी। यानी कॉलोनाइजर ने फीस के तौर पर लाखों का प्लॉट दे दिया था। जिस पर अहमदी परिवार ने आलीशान महल बनवाया था। महल के निर्माण में कॉलोनाइजर का पूरा सहयोग रहा था। रिटायरमेंट के बाद इस महल में बसे अहमदी परिवार की सुरक्षा के लिए 3 शिफटों में 8-8 पुलिसकर्मी तैनात किये जाते थे। यह सारा

अरावली संरक्षण को ठेंगा दिखाता डिलाइट होटल का निर्माण कार्य

घटनाक्रम 1992 से पहले का है जिसका विस्तृत विवरण 'मजदूर मोर्चा' के तत्कालीन अंकों में प्रकाशित किया गया था। अहमदी को यहां बसाने के पीछे कॉलोनाइजर का उद्देश्य था कि इससे उसकी कालोनी में प्रतिष्ठा एवं साख बढ़ने के साथ सुरक्षा भी बढ़ जायेगी, हालांकि बाद में अहमदी उस महल को बेचकर चलते बने।

अहमदी ही वह कारण है जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने 1992 तक बने मकानों को छोड़ने व बाद में बने मकानों को तोड़ गिराने के आदेश दिये हैं। यहां गौरतलब बात यह भी है कि कांत एन्कलेव में बने तमाम मकान सरकार की मंजूरी से व नक्शा आदि पास कराकर बनाये गये हैं। कईयों ने तो इनके लिये बैंकों से भारी कर्ज भी लिया है।

इससे भी गंभीर बात तो यह है कि एक ओर तो सुप्रीम कोर्ट वैध घरों को तुड़वा रही है दूसरी तरफअवैध निर्माण लगातार अरावली में हो रहे हैं। निर्माण पर पूरी पाबंदी के बावजूद अनखीर-सूरजकुंड रोड पर डिलाइट वालों का पंचतारा होटल बड़ी तेजी से बनता आ रहा है। यह बेसमैंट से निकल कर तेजी से ऊपरी मंजिलों की ओर बढ़ता जा रहा है। यह अवैध निर्माण न तो सुप्रीम कोर्ट को दिखाई दे रहा है न एनजीटी को। नगर निगम व तमाम स्थानीय अधिकारियों को तो दिखना ही क्या है।

विदित है कि अरावली संरक्षित क्षेत्र में निर्माण कार्य की थोड़ी सी हलचल होते ही जंगलात, पर्यावरण तथा खनन विभाग वाले टूटकर पड़ते हैं। पानी के लिए बोरिंग मशीन लगाते ही पुलिस वाले टूटकर पड़ते हैं। लेकिन यहां न तो वन विभाग न पर्यावरण न खनन वाले पहुंचे। पानी के लिए 8 बोर होने पर भी पुलिस वाले पास नहीं फटके।

जाहिर है सबने अपने-अपने हिस्से की लूट वसूल कर ली होगी। इस क्षेत्र में निर्माण करने के लिए शासक वर्ग ने एक चोर रास्ता छोड़ा हुआ है। 'अनापति प्रमाण पत्र' यानी एनओसी प्राप्त करके कोई भी यहां कुछ भी कर सकता है। सरकार एवं न्यायपालिका जितनी सख्त होगी एनओसी प्रदान करने वालों के भाव भी उतने ही बढ़ेंगे। पिछले दिनों एनजीटी में इसके निर्माण से संबंधित चले केस के दौरान हरियाणा प्रदूषण बोर्ड ने अपना एनओसी वापस ले लिया था लेकिन उसके बावजूद होटल का काम जारी है। यानी एनओसी एक बार रद्द होने के बाद दोबारा जारी करने के भाव और अधिक बढ़ गये। बाकी कुछ नहीं बदला।

पुलिस को नेतृत्व विहीन रखेंगे खट्टर!

मजदूर मोर्चा ब्यूरो: कानून व्यवस्था के मोर्चे पर बुरी तरह असफल रही हरियाणा की खट्टर सरकार ने फिर भी किसी कठपुतले को ही राज्य पुलिस का डीजीपी बनाने की ठानी हुयी है। इसके लिए, सुप्रीम कोर्ट और संघ लोक सेवा आयोग की निगरानी से बचने के प्रयास में आनन-फानन में विधान सभा का एक दिन का सत्र बुलाकर हरियाणा पुलिस एक्ट में संशोधन करा लिया गया है। इसके मुताबिक पद के योग्य अफसरों की छानबीन का काम अफसरों की एक कमेटी और अंतिम चयन राज्य सिक्यूरिटी कमीशन के जिम्मे कर दिया गया है। इस कमीशन में नेता विपक्ष को छोड़कर सभी खट्टर के 'यस मैन' ही होंगे।

फिलहाल इस पद पर काबिज बलजीत सिंह संधू रिटायर होने के बाद दिहाड़ी पर चलाये जा रहे हैं और खट्टर सरकार को लगता है कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उनका इस तरह एहसानमंद होना भाजपा को माफिक आएगा। इन चुनावों में जाट बनाम गैर-जाट का समीकरण बनाने को आतुर भाजपा सरकार प्रदेश में दो बार अपने कट्टर मतदाताओं तक को दंगाइयों के रहमो-करम पर छोड़ चुकी है। जाट आरक्षण आन्दोलन में संधू के नेतृत्व में ही रोहतक में पुलिस मैदान छोड़ कर भाग निकली थी और स्थानीय पंजाबी व बनिया समुदाय के लोग लुटते-पिटते रहे थे। राम-रहीम की सजा के समय तो स्वयं संधू डीजीपी थे और ऐन उनकी नाक के नीचे पंचकुला में हजारों उपद्रवियों को स्थानीय शहरियों को आतंकित करने दिया गया था।

फिलहाल अपनी ढुलमुल नीति से खट्टर ने हरियाणा पुलिस में अनिश्चितता का जो माहौल खड़ा कर दिया है, उससे पुलिस अपने पेशेवर काम में और दिशाहीन ही होती जायेगी।

श्रमिकों को बांटने पर उतारू वाम

मजदूर मोर्चा ब्यूरो: 7-8 जनवरी को देश एक वार्षिक पाखंड से लबाबब अनुष्ठान का दर्शक होने जा रहा है। यह अवसर होगा तमाम वाम दलों की श्रमिक मांगों को लेकर होने वाली वार्षिक हड़ताल का। विडम्बना यह कि एक ओर इसे श्रमिक एकता का प्रदर्शन बनाकर पेश किया जाएगा और दूसरी ओर इसमें भाग लेने वाले तमाम वाम दल अपने-अपने अलग राग भी गाते रहेंगे।

दरअसल इस अवसर पर वाम दलों का श्रमिकों को बांटने वाला चेहरा ज्यादा उभर कर सामने आता है। श्रमिक ही नहीं आम जन भी यह समझ ने असमर्थ हैं कि संसदीय लोकतंत्र के युद्ध में कई कम्युनिस्ट दलों के उतरने का क्या मतलब हुआ? वे एक दूसरे का तो नुकसान करती ही हैं उन मतदाताओं को भी हतोत्साहित करती हैं जो वाम नीतियों को चाहते हैं पर अपना वोट खराब नहीं करना चाहते। लिहाजा कार्पोरेट परस्त दल सत्ता में काबिज रहते हैं और लगातार श्रमिक विरोधी नीतियां कायम रहती हैं।

उदाहरण के लिए मोदी सरकार ने कारखानों में इंस्पेक्टरों के माध्यम से सरकारी निगरानी यह कह कर बंद कर दी कि इस क्रम में रिश्वत का बाजार गर्म रहता है। इस प्रकार सरकार ने श्रमिक कानूनों को लागू करने की अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ लिए। सवाल है कि सरकारी निगरानी तो श्रमिक के हक में है लेकिन मालिक और इन्स्पेक्टर के बीच की रिश्वतबाजी नहीं, वाम संगठनों को एक पारदर्शी निगरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग उठानी चाहिए। लेकिन वे आगामी हड़ताल में श्रमिक कानूनों को लागू करने की मांग तो उठाएंगे लेकिन पहले से मौजूद निगरानी व्यवस्था को ठीक करने की नहीं।

श्रमिकों को बाँट कर ही कम्युनिस्ट पार्टियों के रहनुमा अपनी-अपनी दूकान चला रहे हैं। वे जब तक बाँटते रहेंगे, उनकी यह बंदरबांट भी बेरोकटोक चलती रहेगी।

आजादी के बाद या सियासी लोग पनपे हैं या चोर पनपे हैं

जाट समाज द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में महाकवि रघुवंशी ने कहा

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिनांक 23 दिसम्बर को जाट समाज की ओर से सैक्टर 16 स्थित किसान भवन में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें शहर के लगभग 100 स्कूलों के उन बच्चों को सम्मानित किया गया जो बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं तथा 12वीं कक्षा की परीक्षा में अपने स्कूल में प्रथम रहे। ऐसे करीब 150 बच्चों को 2100 रुपए का चैक, ट्राफी तथा प्रमाण पत्र देकर उनका उत्साह बढ़ाया गया। इन बच्चों में आधे से अधिक सरकारी स्कूलों के बच्चे थे। बच्चों को सम्मानित करने के लिए स्थानीय विधायक एवं उद्योग मंत्री विपुल गोयल को बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया था। किसान भवन में आयोजित इस समारोह में अनेकों सेवानिवृत अधिकारियों, गणमान्य नागरिकों व महाकवि दिनेश रघुवंशी को भी बुलाया गया था। किसान भवन में और वह भी जाट समाज द्वारा आयोजित समारोह में किसान और किसानों के रहबर सर छोटूराम व पूर्व पीएम चरण सिंह की चर्चा होनी तो लाजमी थी ही, सो हुई भी खूब। इसी दौरान रघुवंशी ने अपना यह मुक्तक कहा:

किसानों की तबाही पर मुनाफाखोर पनपे हैं।
जमाखोरी जो करते हैं वो चारों ओर पनपे हैं।
हुए आजाद हम जब से
हमारे देश में तबसे
सियासी लोग पनपे हैं।
या केवल चोर पनपे हैं।

अन्तिम दो लाइनें पढ़ते वक्त कवि ने मंच पर बैठे मंत्री विपुल गोयल को सम्बोधित करते हुए विशेष तौर से कहा ''विपुल भाई जरा कड़वी बात है ध्यान से सुनना।''

विपुल ने इसे पूरे ध्यान से सुना भी और जवाब में कहा कि यह बिल्कुल ठीक है लेकिन रघुवंशी भाई यह बताना भूल गये कि यह सब बीते 60 वर्षों तक राज कर चुके लोगों पर ही लागू होता है। इसके साथ ही मंत्री जी ने पीएम मोदी व सीएम खट्टर का यशोगान एवं फर्जी उपलब्धियां गिनानी शुरू कर दीं। लेकिन यह जो जनता है न यह जानती है कि लूट की न कोई कसर उन्होंने छोड़ी थी और न अब ये छोड़ रहे हैं।

विधायक मूलचंद ने 200 बैड के अस्पताल का जुमला छोड़ा

बल्लभगढ़ (म.मो.) भारतीय जुमला पार्टी के स्थानीय विधायक जुमलेबाजी में भला क्यों किसी से पीछे रहने लगे। जब सांसद कृष्णपाल गूजर उद्योग मंत्री विपुल गोयल तथा विधायक सीमा त्रिखा इस चुनावी वर्ष में जुमलों की झड़ी लगा सकते हैं तो भला यहां के विधायक मूलचंद शर्मा क्यों पीछे रहने लगे। महिला कॉलेज सहित अन्य कई जुमले छोड़ने के बाद अब उन्होंने 200 बैड का नया अस्पताल खोलने का जुमला छोड़ा हैं सुधी पाठकों ने पढ़ा होगा कि पिछले दिनों सांसद गूजर ने भी ओल्ड फरीदाबाद में एक मल्टी स्पेशिलिटी अस्पताल खोलने का जुमला छोड़ा था। उससे पहले तिगांव में छोटे स्वास्थ्य केन्द्र की जगह उन्होंने बड़े स्वास्थ्य केन्द्र की इमारत का शिलान्यास किया था। जबकि मौजूदा किसी भी स्वास्थ्य केन्द्र, डिस्पेंसेरी एवं अस्पताल में न तो पर्याप्त डाक्टर है न अन्य स्टाफ। इसके बावजूद ये जुमलेबाज आये दिन नये-नये अस्पताल बनाने के जुमले छोड़ रहे हैं।

इस विषय पर 'मजदूर मोर्चा' ने विधायक महोदय से पूछा कि जब आपके घर के निकट स्थित सैक्टर-8 का 200 बैड वाला अस्पताल बना खड़ा है तो उसे क्यों नहीं ठीक से चलवाते अपनी सरकार से? उनका बड़ा मासूम सा जवाब था कि वह तो ईएसआईसी का है जिसमें प्राईवेट (जो ईएसआईसी कवर्ड नहीं है) लोग तो नहीं जा सकते। उन्हें यह समझाने का प्रयास भी किया गया कि उनके क्षेत्र में 5 लाख से अधिक परिवार ईएसआईसी कवर्ड हैं और इस अस्पताल को चलाने का पूरा जिम्मा हरियाणा सरकार का है। तमाम तरह की भर्ती व खरीददारी पूरा जिम्मा हरियाणा सरकार का है जबकि कुल बजट का 88 प्रतिशत ईएसआईसी खर्च करती है। लेकिन अज्ञानता की चादर ओढ़े हुए विधायक महोदय की समझ में कुछ नहीं बैठ रहा था।

दरअसल इन नेताओं का उद्देश्य जनहित न होकर जनता को बेवकूफ बनाना भर है। ये लोग केवल जुमलेबाजी के द्वारा लोगों को बहकाकर किसी तरह सत्ता हासिल कर लेना चाहते हैं। इसके अलावा ईएसआईसी के अस्पतालों में जनता का इलाज तो बेहतर हो सकता है परन्तु ईएसआईसी के नियमों एवं नियन्त्रण के चलते इनमें राज्य सरकार एवं नेताओं की दादागिरी बहुत अधिक नहीं चल पाती। दूसरे चले-चलाये अस्पताल में सुधार करके उसे ठीक ढंग से चलाने को ये लोग अपनी उपलब्धि में गिना नहीं पाते जबकि किसी नई बनी इमारत को ये अपनी उपलब्धि के तौर पर गिना सकते हैं।

दरअसल, मूलचंद जैसों की राजनीति में आम आदमी के नजरिए से सोचने का रिवाज ही नहीं रहा।